

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 114/VII-1/2018/14 ख/11
देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम चिफलेत पाली चक टिटोली में 4.822 है० क्षेत्रफल पर सोपस्टोन का पट्टा चाहने हेतु श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, ग्राम कुनेडा, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-272/VII-1/14-ख/2011, दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, ग्राम कुनेडा, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम चिफलेत पालीचक टिटोली में 4.822 है० में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1409/VII-1/14-ख/2011, दिनांक 8 सितम्बर, 2016 द्वारा उक्त आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु 03 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-3076/मु०ख०/06/बाग०/खनन/2009-10, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम कुनेडा, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम चिफलेत पालीचक टिटोली में 4.822 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.3.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8.9.2016 की अनुपालना में हुए लगभग 15 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम चिफलेत पालीचक टिटोली में 4.822 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	ग्राम पालीचक, टिटोली एवं चिफलेत में जोतदार के नाम 4.769 है०, सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.053 है० कुल 4.822 है० भूमि एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तें:

- 7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।
- 7.2. वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

- 7.3. आवेदक को खनन के दौरान विलेख की शर्तों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- 7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि कुल रकवा 0.053 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
- 7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
- 7.6. आवेदक द्वारा जिला पर्यावरणीय समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति सं० 04/DEIAA/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7.7. आवेदक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।
- 7.8. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू-स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 7.9. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या: 414 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, ग्राम कुनेडा, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव